हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

त्रिलोक चंद और अन्य।

(आपराधिक अपील सं 2011 का 2133-2134) जनवरी 17,2008

[एनवी रमना और एस अब्दुल नाज़र, जेजे।]

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट,1985- धारा 55-निषिद्ध माल-वसूली-उत्तरदाताओं-अभियुक्तों को धारा 20 के तहत दोषसिद्धि और 10 साल के कठोर कारावास की सजा -उच्च न्यायालय द्वारा बरी करना-उच्च न्यायालय के आधार पर बरी किए जाने के खिलाफ राज्य की अपील अभियोजन मामले में छोटी-मोटी विसंगतियों को अधिक महत्व दिया और बिना कोई ठोस कारण बताए अभियुक्तों की अपील को स्वीकार कर लिया - माना गया: अभियोजन मामले में जिन विसंगतियों को उजागर किया गया, वे डीडब्ल्यू-1 के साक्ष्य थे कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पुलिस अधिकारियों ने उसे लोड करने के लिए कहा था परित्यक्त घर के बाहर पड़ी बोरियां, स्वतंत्र गवाहों के इस आशय के साक्ष्य कि घटना के समय वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और कुछ कागजात पर उनके हस्ताक्षर लिए गए थे- ये विसंगतियां थीं चरित्र में प्रमुख - साक्ष्य में यह स्थापित करने के लिए समर्थन का अभाव है कि कथित तारीख और समय पर अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तरीके से आरोपी के कब्जे से वास्तव में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई थी - साथ ही अभियोजन मामले में विसंगतियों की संख्या को देखते हुए अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरोधाभासी बयान, अभियोजन की कहानी संदेहपूर्ण प्रतीत होती है - अभियोजन उचित संदेह से परे आरोपी द्वारा कथित अपराध को स्थापित करने में विफल रहा है, आरोपी-प्रतिवादियों को संदेह का लाभ दिया जाता है - बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. रिकॉर्ड से पता चला कि एन.डी.पी.एस. की धारा 55 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अधिनियम, मामले की संपत्ति के अनुसार पुलिस द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। निर्धारित प्रपत्र में, जब्ती का स्थान नगवेन के रूप में उल्लिखित था, न कि पनारसा ब्रिज के रूप में और केवल एक आरोपी का नाम दिखाया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि उसे ले जाते समय तीन बोरियां जब्त किया गया था। इस तथ्य को सही ठहराने के लिए बाद में अन्य आरोपियों का नाम जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक समय में प्रतिबंधित सामग्री के तीन बैग नहीं ले जा सकता था। अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरोधाभासी बयानों के साथ-साथ अभियोजन मामले में कई विसंगतियों को देखते हुए, अभियोजन की पूरी कहानी खराब हो गई और इसके संस्करण को बदनाम करने का कारण बना। गवाहों के बयानों में विरोधाभास मामले के लिए घातक है, हालांकि उनके साक्ष्य में मामूली विसंगतियां या भिन्नता प्रतिकूल नहीं होगी। मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि विसंगतियाँ तुलनात्मक रूप से प्रमुख हैं और अभियोजन की कहानी की जड़ तक जाती हैं। इसलिए अभियोजन मामले को अनुचित महत्व देने के लिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय अनाज से भूसा छान सकता है और गवाहों की गवाही से सच्चाई का पता लगा सकता है। साक्ष्य पर विश्वसनीयता की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए और इसे उक्त साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए न्यायालय के में विश्वास जगाना चाहिए [पारस 11,12] [260-सी-जी]

2. सबूत कम हैं और यह स्थापित करने के लिए समर्थन की कमी है कि कथित तारीख और समय पर अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तरीके से उत्तरदाताओं के कब्जे से वास्तव में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था। यह आवश्यक है कि न्यायालय को एन.डी.पी.एस. के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि देने के लिए कानून का पालन करना चाहिए। अधिनियम "कठोर सज़ा है, सबूत जितना सख्त है।" ऐसे मामलों में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की बहुत ही उत्साहपूर्वक जांच की जानी चाहिए गलत निहितार्थ की हर

संभावना को बाहर रखें। लेकिन, मौजूदा मामले में, मौजूदा परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष की कहानी पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आरोपी-प्रतिवादियों को सजा मिलेगी। वे संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं। [पैरा 13][261-ए-सी]

हिमाचल प्रदेश राज्य वी. लेख रा) (2000) 1 एससीसी 247: [1999] 4 आपूर्ति एससीआर 286;

सुखदेव यादव बनाम बिहार राज्य (2001) ब एससीसी 86: [2001] 3 पूरक। एससीआर 91-भरोसेमंद पर

केस लॉ संदर्भ [1999] 4 पूरक। एससीआर 286 पैरा 12 [2001] 3 सप्ल पर निर्भर था। एससीआर 91 पैरा 12 हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम त्रिलोक चंद पर भरोसा करता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 2011 की संख्या 2133-2134।

2006 की आपराधिक अपील संख्या 220 और 348 में शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.10.2009 से।

अपीलकर्ता के लिए डी. के. ठाकुर, एस. अहमद, वरिंदर कुमार शर्मा, नरेश के. शर्मा, सलाहकार।

उत्तरदाताओं के लिए एस.एस. रे, वैभव जी. सुश्री राखी रे, सलाहकार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एन. वी. रमना, जे. 1. ये अपीलें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14 अक्टूबर, 2009 के फैसले और आदेश से व्यथित होकर राज्य द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें आरोपी-प्रतिवादियों द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर आपराधिक अपीलों को अनुमति दी गई है। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (संक्षेप में "एनडीपीएस अधिनियम") के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा। उक्त आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय ने आरोपी-प्रतिवादियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया।

2. इन अपीलों की खूबियों की सराहना करने के लिए, अभियोजन मामले से सामने आए संक्षिप्त तथ्यों को शुरुआत में ही नोट करने की जरूरत है। 10 जुलाई, 2004 को, अंजनी कुमार, इंस्पेक्टर, सीआईडी, शिमला (पीडब्लू12) को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग चरस का अवैध कारोबार कर रहे हैं, एएसआई जियान चंद (पीडब्लू 9) और कांस्टेबल राकेश के साथ पनारसा ब्रिज की ओर बढ़े। कुमार (पीडब्लू 8) और कुछ अन्य पुलिस कर्मी। अमर चंद (पीडब्लू 1) और कुलदीप कुमार (पीडब्लू 2) जो उस समय उस रास्ते से जा रहे थे, भी गवाह के रूप में उनके साथ शामिल हो गए। रात करीब 11.30 बजे. रात में, आरोपी-प्रतिवादी अपने साथ तीन बोरी प्रतिबंधित पदार्थ (चरस) लेकर उस स्थान पर पहुंचे और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से तस्करी का सामान जब्त कर सैंपल तैयार कर सीलबंद कर निशानदेही की और मामला दर्ज कर लिया। जांच के बाद, आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और उनके इनकार करने पर मामला सुनवाई के लिए सौंप दिया गया।

3. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया एन.डी.पी.एस. कार्यवाही की और उन्हें दस वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक को 1,00,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी दो साल की कैद ।

4. ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित होकर, अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और उच्च न्यायालय ने सबूतों का विश्लेषण करने के बाद उनकी अपील को स्वीकार कर लिया और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति आदेश से असंतुष्ट राज्य हमारे समक्ष अपील में है

5. हमने अपीलकर्ता-हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को भी सुना है, और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

6. राज्य के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तों की अपीलों से निपटते समय, उच्च न्यायालय ने अभियोजन मामले में तुच्छ विसंगतियों को अधिक महत्व दिया है। आधिकारिक गवाहों द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों को नजरअंदाज करते हुए, उच्च न्यायालय ने बस यह माना कि उनके बयानों में भौतिक विरोधाभास थे और बिना कोई ठोस कारण बताए आरोपियों की अपील की अनुमति दे दी और इस तरह कानून की गलती की।

7. हालाँकि, आरोपी-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आरोपी को बरी करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया।

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद, हम अभियोजन मामले में निम्नलिखित विसंगतियों को देखते हैं, जो हमारी सुविचारित राय में, मौजूदा मामले से निपटने में अधिक महत्व रखती हैं

(1) तुलसी राम (डीडब्ल्यू 2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि घटना के दिन ले. 10-7- 2004, शाम करीब 4/5 बजे जब वह पनारसा पुल से होकर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में पनारसा पुल के पास पुलिस अधिकारी उससे मिले। उन्होंने उससे एक परित्यक्त घर के बाहर पड़े तीन बोरे वाहन में लोड करने के लिए कहा। तदनुसार, वह दो बोरियां ले गया, जबकि एक बोरा पुलिस अधिकारियों ने उठाया और वाहन में लोड किया। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि बैग में प्रतिबंधित सामग्री 'चरस' थी और उसे परित्यक्त घर से बरामद किया गया था।

जीआई) पीडब्लू 1 (अमर चंद) और पीडब्लू 2 (कुलदीप कुमार) जिन्हें स्वतंत्र गवाह कहा गया था, ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब घटना घटी तो वे मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने अपनी उपस्थिति में आरोपी-प्रतिवादियों को हिरासत में लेने और आरोपियों से प्रतिबंधित सामग्री की कथित बरामदगी से इनकार किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और कुछ कागजात पर उनके हस्ताक्षर लिए गए थे। इसके अलावा, उन्होंने स्वीकार किया है कि पहले भी कुछ अन्य मामलों में पुलिस ने उन्हें अभियोजन गवाह के रूप में इस्तेमाल किया था।

(iii) पुलिस अधिकारियों के बयान के अनुसार पीडब्लू 9 (ज्ञान चंद) को 10" और 11" जुलाई, 2004 की मध्यरात्रि को तराजू और बाट उधार लेने के लिए दुकानदार हेम राज (पीडब्लू5) के पास भेजा गया था, और जब्त की गई सामग्री भेज दी गई थी। मालखाने को. इसके विपरीत, पीडब्लू 5 (हेम राज) ने कहा कि 11 जुलाई, 2004 को सुबह 9 या 10 बजे पुलिस अधिकारियों द्वारा तराजू और बाट उससे उधार लिए गए थे। उक्त पीडब्लू5 को भी शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था। इतना ही नहीं, अंजनी कुमार (पीडब्लू 12) के अनुसार, ज्ञान चंद (पीडब्लू 9) रात 11.30 बजे तराजू और बाट लेने के लिए मौके से चले गए। रात 8.15 बजे, पूर्व समय पर घटनास्थल पर लौटे। जबकि एक अन्य गवाह कांस्टेबल राकेश कुमार (पीडब्लू 8) ने बताया कि ज्ञान चंद (पीडब्लू 9) दोपहर 1 बजे स्केल और बाट लाने के लिए मौके से निकला था।

(iv) अंजनी कुमार (पीडब्लू 12) के अनुसार, उन्होंने राजिंदर कुमार (पीडब्लू 11) को अपने सेल फोन पर बुलाया और कुल्लू में उनके साथ शामिल होने के लिए कहा, जबकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि राजिंदर कुमार (पीडब्लू 11) पनारसा में पीडब्लू 12 में शामिल हो गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से पीडब्लू 12 से कोई कॉल प्राप्त होने से इनकार किया।

(v)आरोपी-प्रतिवादियों का मामला यह है कि जब वे एक ढाबे पर चाय पी रहे थे, पुलिस वहां पहुंची और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई और मामले में झूठा फंसा दिया। यह तथ्य एक चाय विक्रेता, बिहारी लाल (डीडब्ल्यू 3) के बयान से पुष्ट होता है, जिसने कहा था कि 11-7-2004 को पुलिस अधिकारी उसकी दुकान पर आए और आरोपी को ले गए।

9. उपरोक्त उल्लिखित अपर्याप्तताओं के अलावा, मामले के अन्य पहलुओं से संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा कुछ अन्य विरोधाभासी बयान भी हैं, राकेश कुमार (पीडब्लू 8) के अनुसार, वह रिपोर्ट (एक्स.पीएच) को पुलिस स्टेशन ले गए थे। एक ट्रक में, जबकि पीडब्लू-9 (गैलन चंद) का कहना है कि पीडब्लूबी ने एक स्कूटर से यात्रा की और शीर्ष गवाह अंजनी कुमार (पीडब्लू12) का कहना है कि पीडब्लूबी पुलिस स्टेशन गया और पैदल ही घटनास्थल पर लौटा।

10. अभियोजन मामले में एक और महत्वपूर्ण विसंगति जो पुलिस अधिकारियों की सत्यता पर संदेह पैदा करती है, वह यह है कि, जैसा कि अंजनी कुमार (पीडब्लू 12) ने बताया था, छह नमूना पार्सल के साथ जब्त की गई पूरी संपत्ति गांधी राम के पास जमा की गई थी (पीडब्लू 6) ।जबकि दबे राम, एसएचओ (पी डब्लू 4) का कहना है कि अंजनी कुमार (पी डब्लू 12) ने रात 8.30 बजे उनके सामने तीन बैग और तीन सैंपल पार्सल पेश किए। दूसरी ओर, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री भी गलत साबित होती है क्योंकि प्रासंगिक समय पर, पीडब्लू 12 सदर पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मंडी और पुलिस अधीक्षक को विशेष रिपोर्ट भेजी (एक्स. पीडब्लू 11/A)।

11. रिकार्ड से यह भी प्रतीत होता है कि एन.डी.पी.एस. की धारा 55 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अधिनियम, मामले की संपत्ति के अनुसार पुलिस द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि विहित प्रपत्र में जब्ती का स्थान नगवाईन अंकित था न कि पनारसा पुल तथा केवल एक अभियुक्त 1.ई. का नाम अंकित था। संतोष कुमार को दिखाया गया जिसके पास से प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई थी, जबकि वह तीन बोरियां ले जा रहा था। जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य को सही ठहराने के लिए अन्य अभियुक्तों का नाम बाद में जोड़ा गया था कि एक व्यक्ति एक समय में प्रतिबंधित सामग्री के तीन बैग नहीं ले जा सकता था।

12. अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरोधाभासी बयानों के साथ अभियोजन मामले में विसंगतियों की संख्या को देखते हुए, अभियोजन की पूरी कहानी खराब हो जाती है और इसके संस्करण को बदनाम करने की ओर ले जाती है। गवाहों के बयानों में विरोधाभास मामले के लिए घातक हैं, हालांकि उनके साक्ष्य में मामूली विसंगतियां या भिन्नता प्रतिकूल नहीं होगी [देखें: एच.पी. राज्य बनाम लेख राज (2000) 1 एससीसी 247]। मामले की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि विसंगतियाँ तुलनात्मक रूप से प्रमुख हैं और अभियोजन की कहानी की जड़ तक जाती हैं। इसलिए हम अभियोजन मामले को अनावश्यक महत्व देने के लिए उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय अनाज से भूसा छान सकता है और गवाहों की गवाही से सच्चाई का पता लगा सकता है। साक्ष्य को विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से माना जाना चाहिए और एक बार जब वह संतुष्ट हो जाए, तो उसे कथित साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए न्यायालय के मन में विश्वास जगाना चाहिए

13. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी-प्रतिवादियों द्वारा कथित अपराध के कमीशन को स्थापित करने में विफल रहा है। सबूत कम हैं और यह स्थापित करने के लिए समर्थन की कमी है उक्त तिथि और समय पर अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तरीके से उत्तरदाताओं के कब्जे से वास्तव में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई थी। यह आवश्यक है कि न्यायालय को एन.डी.पी.एस. के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि देने के लिए कानून का पालन करना चाहिए। अधिनियम "कठोर सज़ा है, सबूत जितना सख्त है।" ऐसे मामलों में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की बहुत उत्साहपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि झूठे आरोप की हर संभावना को बाहर किया जा सके। लेकिन, मामले में. उपरोक्त स्पष्ट परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष की कहानी पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त-प्रतिवादियों को दोषसिद्धि प्रदान की जाएगी। वे संदेह का लाभ पाने

के पात्र हैं। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं और इसमें दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

14. तदनुसार, आपराधिक अपीलें खारिज की जाती हैं।

अपील खारिज.

सर्वम द्विवेदी